संख्या : 1870/IV(2)-शा0वि0-80(सा0)-2014

प्रेषक.

डी०एस० गर्बाल, सचिव. उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुमाग-2

देहरादूनः दिनांक 🛭 दिसम्बर, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरपालिका परिषद, बागेश्वर को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत घनराशि की स्वीकृति।

महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, बागेश्वर के पत्रांक-184/निर्माण-आगणन/2014-15. दिनांक 02.09.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव/आगणन उपलब्द कराते हुए अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, बागेश्वर को निम्नलिखित 02 निर्माण कार्यों हेतु टी०ए०सी० (वित्त विभाग) की संस्तुतिनुसार कुल ₹14.25 लाख (रूपये चौदह लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-(मनराशि र लाख में)

क्र.स कार्य का विवरण स्वीकृत धनराशि गुरुद्वारा से जूना अखाड़ा तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य। 1. 9.47 विनोद भट्ट के मकान से नदीगांव तक रैलिंग निर्माण कार्य। 2 4.78 योग-14.25

- उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :-2-
- उक्त धनराशि ₹ 14.25 लाख (रूपये चौदह लाख पच्चीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर ı. शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, बागेश्वर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी।
- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में H. पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- स्वीकृत कार्यं कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, III. 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणदत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के IV. अनुरूप कराये जायेंगे।
- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप V. से उत्तरदायी होंगे।
- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा VI. उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो VII. उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धृतराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। ..2/-....

मुख्य संचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते VIII. समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वास जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability IX. Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

धनराशि का दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। X.

उक्त के संबंध में होने दाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डी को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विमाग के अशा0पत्रसं0- 510/XXVII(2)/2014, दिनांक 05.12.2014 में प्राप्त जनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-5_14-12-1301.17 ... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

> (डी०एस० गब्यलि) सचिव।

सं0- 16-0(1)/10(2)-श0वि0-2014, तद्दिनांक। प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

निजी सचिव, मां० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी। 2

निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल। 4.

जिलाधिकारी, बागेश्वर।

वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

विता अनुभाग-2/संयुक्त निर्देशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जीठओठ में इसे शामिल करें।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बागेश्वर।

बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून। 10.

गार्ड बुक । 12.

> ओमकार सिंह) उप सचिव।

उपना से